हो गयी मोदी की जीएसटी व्यवस्था फेल...

केरल के साथ देश के नौ राज्य केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मे पिटीशन दाखिल करने वाले हैं। केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने कहा कि जीएसटी मुआवज़े के बदले कर्ज़ लेने के विकल्प के विरोध में केरल सुप्रीम कोर्ट जाएगा. उसके साथ नौ और राज्य भी शामिल होंगे।

केंद्र सरकार जीएसटी मुआवज़े की भरपाई के लिए राज्यों को भारतीय रिज़र्व बैंक से कर्ज़ लेने के दो विकल्प दे रही हैं। 12 राज्यों ने केंद्र सरकार द्वारा दिए गए समाधान को स्वीकार कर लिया लेकिन नौ राज्य दोनों विकल्प स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है इसे लेकर एक हफ़्ते में दो बार जीएसटी काउंसिल की बैठक हो चुकी है ओर कोई सहमति नही बन पाई। बैठक में वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों के जीएसटी राजस्व में कमी की भरपाई के लिये केन्द्र सरकार बाजार से कर्ज नहीं उठा सकती है क्योंकि इससे बाजार में कर्ज की लागत बढ़ सकती है ।

दरअसल वित्तमंत्री का कहना गलत है क्योंकि केंद्र अधिक सक्षम है. जब केंद्र उधार लेता है, उसे कम ब्याज दर पर कर्ज मिल जाएगा जबकि राज्यों को अधिक ब्याज चुकाना होगा और रही बाजार में कर्ज की लागत की बात तो ऐसी कोई गारण्टी नही है कि कर्ज राज्य लेंगे तो लागत नही बढ़ेगी।

ये नौ राज्य चाहते हैं कि जीएसटी राजस्व में कमी की भरपाई के लिये केंद्र सरकार कर्ज ले, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने पिछले दिनों ट्विटर पर चिट्ठी शेयर करते हुए लिखा कि 'GST मुआवजे की भरपाई के लिए राज्यों को उधार का विकल्प दिया जाना GST को संवैधानिक रूप से लागू किए जाने से पहले हुए समझौते की भावना से मेल नहीं खाता है.' अगर राज्य उधार लेंगे तो इसे चुकाने का बोझ बढ़ जाएगा और वो पहले ही आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं।

केंद्र सरकार राज्यों को जीएसटी मुआवजा देने की अपनी जिम्मेदारी निभाने का वादा तोड़ने की स्थिति में है। अब राज्यो के पास इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने के अलावा कोई चारा नही बचा है। केंद्र और राज्यों के बीच जारी यह विवाद जीएसटी के अंत की शुरुआत सिद्ध हो सकता है।

प्रो. उदयवीर सिंह जी की याद में

प्रोफेसर उदयबीर सिंह
5 दिसम्बर 1946-3 अक्टूबर 2020

उदयवीर प्रिय मित्र आप के
जाने का समाचार
मुझ जैसे दुर्बल - हृदयों को
गया जान से मार।

माना बंधा हुआ है यम के
नियमों से संसार
फिर भी मित्र-बिछोह का सागर
होता नहीं है पार।

जीवन की क्षणभंगुरता का
मन में उठा विचार
सच है विधाता के हाथों में
सारा दारोमदार ।

बार बार आता है मन में
यही एक विचार
इतनी जल्दी जाना था तो
काहे बढ़ाया प्यार ।

कैसे बताऊं मित्र आप के
जाने के उपरान्त
एक अकेलापन सा मन में
छाया रहता नितान्त ।

जो बातें होती थीं आप से
अब वह बात कहां
एक आदमी गया क्या खाली
सा हो गया जहां ।

दूरभाष पर रोज परस्पर
मिलते ही थे हम
हाय अचानक छोड़ अकेला
चले गए अब तुम ।

चली गई जीवन की खुशियां
बढ़ने लगे हैं ग़म
गायब सी हो गई रोशनी
छा गया गहरा तम ।

सूर्य उदय अब भी होता पर
उदयवीर के बिन
अंधियारी रातों जैसा ही
अब लगता है दिन ।

याद खूब आती हैं खूबियां
थक जाते गिन-गिन
लगता है जैसे मित्रों का
गया सहारा छिन ।

जिससे जितना अधिक प्यार
मानव के मन में होता
उससे बिछड़ कर उतना अधिक
ज़ार-ज़ार दिल रोता ।

इक दूजे को हम ने परस्पर
बहुत सुनाई कविता
आज कवि और कविता तो हैं
चला गया है श्रोता ।

-डा. रामवीर

अपील

सहयोगी साथियों का धन्यवाद देते हुए मजदूर मोर्चा आपको सूचित करना चाहता है कि कोरोना और लॉकडाउन काल में एक तरफ जहाँ फरीदाबाद के लगभग सभी छोटे अखबार बंद हो गए थे वहीं मजदूर मोर्चा आप सभी के सहयोग एवं पाठकों की मांग और उससे उपजे हौसले के कारण सफलतापूर्वक निष्पक्ष व निडर खबरें प्रकाशित करते रहने में सफल रहा है।

जैसा कि आप जानते हैं पूरा भारत आज भयंकर आर्थिक बदहाली से जूझ रहा है जिससे मज़दूर मोर्चा भी बच नहीं पाया है। इसलिये मज़दूर मोर्चा को आप सभी की मदद की जरूरत है। कृपया अपना मासिक या एकमुश्त आर्थिक सहयोग निम्नलिखित खाते में भेजें ताकि अखबार नियमित निकलता रहे। खाते में पैसा भेजने वालों से निवेदन है कि वे मजदूर मोर्चा को एसएमएस के जरिये सूचित भी कर दें।

नाम-मज़दूर मोर्चा
खाता संख्या-451102010004150
IFSC Code : UBIN0545112
Bank Name : Union Bank of India
Branch : Sector-7, Faridabad - 121006

युवकों का साइकिल अभियान पहुंच रहा है गांव-गांव

सोनीपत (म.मो) रोजगार पर बढ़ते हमलों के खिलाफ गांव में मेहनतकश वर्गों के बीच व्यापक एकता के लिए मजदूर-किसान- नौजवानों को असल मुद्दों से जोड़ने का अभियान है। जिसे 'रोजगार बचाओ साइकिल अभियान' के नाम से चलाया जा रहा है। 18-20 नौजवान छात्र-छात्राएं एक गांव से दूसरे गांव की दूरी को साइकिलों से तय करते हुए हर सुबह निकलते हैं। साइकिल यात्रा के दौरान गांव में पैदल घूम कर हर घर में पर्चा बांटा जाता है, सभा आयोजित की जाती हैं, गीत गाए जाते हैं "बेरोजगारी बड़ी बीमारी फैली बीच हमारे पढ़े लिखे भी भारत के म्ह हांडे मारे मारे", "छोरे म्हारे देश के बूट तुडावैं स, बीए, एमए पास यड़ै सडकां पर पावै से"।

इनकी मांग है- सभी को योग्यता के अनुसार रोजगार दिया जाए, ठेका प्रथा बंद की जाए, सरकारी विभागों में खाली पड़े लाखों पद भरे जाएं, रोजगार न मिलने तक 15000 बेरोजगारी भत्ता दिया जाए,रोजगार के लिए आवेदन शुल्क निशुल्क किया जाए।

प्रदूषण के लिये किसानों की पराली नहीं सरकारी निकम्मापन व भ्रष्टाचार जिम्मेवार है

फ़रीदाबाद (म.मो.) जिंदा रहने के लिये हर जीव को शुद्ध हवा सबसे जरूरी है। कोई भी जीव, भोजन बिना कई हफ़्ते, पानी बिना कुछ दिन निकाल सकता है परन्तु सांस लिये बिना दो मिनट नहीं निकाल सकता। जब सांस लेने वाली हवा ही शुद्ध न होकर प्रदूषित एवं जहरीली हो तो कोई प्राणी कितने दिन जीवित रह पायेगा? यह प्रदूषित वायु एक प्रकार का धीमा जहर है जिसे ग्रहण करके मौत की ओर बढना जनता की मजबूरी हो चुकी है।

पानी सिर से ऊपर निकल जाने के बाद चेती सरकार ने इस प्रदूषण का कारण किसानों द्वारा पराली जलाया जाना बताया हैं। दूसरा कारण लोग़ों द्वारा जनरेटर चलाना व सड़कों पर वाहनों का बढना भी माना जा रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि पराली जलाने से मोदी सरकार के अनुसार चार प्रतिशत तथा अन्य विशलेषकों द्वारा 11 प्रतिशत माना जा रहा है। यदि सरकार ने समय रहते इस ओर ध्यान दिया होता और पराली के इस्तेमाल का सही विकल्प खोजा होता तो यह सब न होता।

रही बात जनरेटरों की तो इनके इस्तेमाल पर सरकार ने बेशक पाबंदी लगा दी है। लेकिन सरकार से कोई यह तो पूछे कि लोग जनरेटर चलाते क्यों हैं? क्या लोग़ों को जनरेटर की अपेक्षाकृत महंगी बिजली जलाना ज्यादा अच्छा लगता है? नहीं, बिल्कुल नही। सरकार की नालायकी, निकम्मेपन व भ्रष्टाचार के चलते बिजली की निर्बाध सप्लाई न मिलने के कारण लोगों को जनरेटरों का सहारा लेना पड़ता है। इसी शहर में अनेकों ऐसी सोसायटियां हैं जिनको बिजली कनेक्शन मिले ही नहीं, वे पूरी तरह जनरेटरों पर निर्भर हैं। किसी समारोह के लिये अस्थाई बिजली कनेक्शन लेने के झंझट में पड़ने की बजाय लोग जनरेटर का सहारा लेना पसंद करते हैं।

सबसे अधिक खतरनाक प्रदूषण धूल उड़ने से होता है धूल के अति महीन कण एक बार हवा में चढ़ जायें तो आसानी से नीचे नहीं गिरते। इस धूल का सबसे बड़ा स्रोत भवन निर्माण सामग्री के अलावा सड़कें, खासकर टूटी सड़कें व उनके कच्चे रेतीले किनारे हैं। इस शहर में शायद ही कोई ऐसी सड़क हो जिस पर बने गड्ढों से धूल न उड़ती हो। रही सही कसर स्मार्ट सिटी के नाम पर खोद मारी सड़कों ने पूरी कर दी है। झाड़ू से उड़ने वाली धूल को रोकने के नाम पर नगर निगम ने करोड़ों रुपये की सकर मशीनों वाले वाहन खरीद डाले जो झाड़ू का काम करते हैं। परन्तु ये सकर मशीने केवल वहां सफल हो सकती हैं जहां सड़कें सही सलामत हों तथा उनके कच्चे किनारों पर मिट्टी न पड़ी हो। यहां जिन हालात में ये सकर मशीने चलाई जा रही हैं, वे शीघ्र ही कबाड़खाने में पहुंच जायेंगी।

सार्वजनिक परिवहन की कमी तथा सड़कों पर पार्किंग की वजह से लगने वाले जाम भी प्रदूषण को खूब बढा रहे हैं। विद्युतचालित ट्रेनों की बजाय सड़क परिवहन को बढावा देकर भी वायु प्रदूषण को बढाया जा रहा है। सरकार द्वारा बनाये गये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उगाही करने वाले संस्थान बन कर रह गये हैं तो प्रदूषण कैसे नहीं बढेगा?

मज़दूरों के लिये तहसीलदार बड़खल के पास नहीं है समय

राजू कन्वर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में काम करने वाले बद्री प्रसाद को कंपनी ने नौकरी खत्म होने पर ग्रेच्युटी के पैसे नहीं दिये लिहाजा बद्री को न्यायालय की शरण में आना पड़ा। ग्रेच्युटी की कन्ट्रोलिंग अथारिटी ने 30/3/2018 को बद्री के पक्ष में निर्णय सुनाते हुये कंपनी को उसे रुपये 149423 मय 12 प्रतिशत ब्याज के देने के आदेश दिये। पर सात-आठ महीने की भाग-दौड़ के बाद भी जब कंपनी ने पैसे नहीं दिये तो बद्री पुन: ग्रेच्युटी न्यायालय की शरण में गया। न्यायालय ने 14/10/18 को कलेक्टर यानी डीसी फ़रीदाबाद को पैसों की रिकवरी के लिये लिखा और डीसी ने एक साल बाद यानी 31/12/19 को तहसीलदार बड़खल को कंपनी से पैसा रिकवर करने को लिखा। अब बद्री तहसीलदार के चक्कर काट रहा है।

रोज मज़दूरों और किसानों के लिये गला फ़ाड़कर चिल्लाने वाली सरकार के डीसी के पास एक मज़दूर की चिट्ठी एक साल तक पड़ी रही तो 9 महीने से तहसीलदार बड़खल उसको दबाये बैठा है। मज़दूर कुल पांच साल से अपने जायज हक को पाने के लिये दर-दर की ठोकरें खा रहा है और अफ़सर अपने वातानुकूलित कमरों में बैठे आराम फरमा रहे हैं। क्या कभी डीसी फ़रीदाबाद और तहसीलदार बड़खल सोचेंगे कि इन्हीं मज़दूरों किसानों की मेहनत की कमाई में से ही उन्हे तनखा मिलती है। क्या बद्री प्रसाद को उसका हक मिल पायेगा।

अजातशत्रु